

आभासी बैंक, अब और नहीं*

एम. राजेश्वर राव

देवियो और सज्जनो!

सीआईआई एनबीएफसी समिट 2024 में आना मेरे लिए खुशी की बात है। सर्वप्रथम, मैं सीआईआई द्वारा आयोजित एनबीएफसी शिखर सम्मेलन के छठे चरण में उद्घाटन भाषण देने के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) पर सीआईआई राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष श्री अभिमन्यु मुंजाल को धन्यवाद देता हूँ।

मुझे याद है कि मैं अक्टूबर 2021 में आयोजित सीआईआई एनबीएफसी समिट में पहले भाषण¹ में इस मंच पर था, मैंने एनबीएफसी सेक्टर में स्केल आधारित नियामक (एसबीआर) दृष्टिकोण की शुरुआत पर बात की थी। तब से काफी समय बीत गया है। एसबीआर ढांचा तब से एनबीएफसी क्षेत्र के लिए शुरू किया गया है और एनबीएफसी ने संशोधित नियमों को निर्बाध रूप से परिवर्तित कर दिया है। जबकि मैंने पहले एसबीआर ढांचे के विस्तृत संदर्भों पर चर्चा की थी, आज मैं एसबीआर ढांचे सहित एनबीएफसी नियमों के पीछे व्यापक नियामक दृष्टिकोणों पर चर्चा करने का प्रस्ताव करता हूँ और फिर एनबीएफसी क्षेत्र से संबंधित कुछ विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ।

वित्तीय क्षेत्र में एनबीएफसी की भूमिका

दिसंबर 2023 में, वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने अपना वार्षिक प्रकाशन 'ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऑन नॉन-बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन'² जारी किया। यह नोट किया गया है कि वैश्विक स्तर पर, गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता (एनबीएफआई) क्षेत्र के आकार में 2022 में 3 प्रतिशत की कमी आई है, जो 2009

* श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण – 09 फरवरी, 2024 – मुंबई में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित एनबीएफसी शिखर सम्मेलन में।

प्रदीप कुमार और अनुज शर्मा द्वारा प्रदान किए गए इनपुट को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाता है।

¹ क्षितिज का पीछा करते हुए (श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई टिप्पणी – 22 अक्टूबर 2021 – \$5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में एनबीएफसी की भूमिका पर सीआईआई एनबीएफसी शिखर सम्मेलन में) https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?id=1135

² <https://www.fsb.org/2023/12/global-monitoring-report-on-non-bank-financial-intermediation-2023/>

के बाद पहली उल्लेखनीय कमी है। हालांकि, इकोनॉमिक फंक्शन 2 (ईएफ 2) संस्थाओं यानी भारत में एनबीएफसी के समान उधार देने वाली गतिविधियों को चलाने वाली संस्थाओं ने लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की है जो एफएसबी द्वारा निगरानी की जाने वाली एनबीएफआई क्षेत्र की सभी पांच आर्थिक श्रेणियों में सबसे अधिक है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत ईएफ2 परिसंपत्तियों का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। व्यक्तिगत देश के स्तर पर, भारत में एनबीएफआई क्षेत्र की कुल वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण देने वाली संस्थाओं से आने वाला सबसे अधिक योगदान है।

इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 2017 और 2022 के बीच पांच साल की अवधि में, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के आधे हिस्से में एनबीएफआई क्षेत्र द्वारा आयोजित कुल वित्तीय संपत्ति की हिस्सेदारी कम हो गई है। तथापि, भारत उन कुछ देशों में से एक है जिसने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित कुल वित्तीय परिसंपत्तियों के हिस्से में वृद्धि दर्शायी है। संक्षेप में, डेटा इंगित करता है कि भारत में एनबीएफसी क्षेत्र आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मार्च 2023 तक, एनबीएफसी क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात 12.6 प्रतिशत था और यह क्षेत्र दस साल पहले (मार्च 2013) के 13 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2023 तक बैंकिंग क्षेत्र की संपत्ति का 18.7 प्रतिशत बन गया है।

भारतीय एनबीएफआई क्षेत्र की एक बहुत ही उल्लेखनीय विशेषता ऋण देने वाली कंपनियों की प्रधानता है। वैश्विक स्तर पर सामूहिक निवेश वाहन जैसे कि, मनी मार्केट फंड्स (एमएमएफ), फिक्स्ड इनकम फंड्स, मिक्स्ड फंड्स, क्रेडिट हेज फंड्स, रियल एस्टेट फंड्स आदि एनबीएफआई सेक्टर की परिसंपत्तियों में करीब 74 फीसदी का योगदान करते हैं, लेकिन भारत का मामला इससे अलग है। यह विशेषता, इस तथ्य के साथ संयुक्त है कि एनबीएफसी ने पिछले कुछ वर्षों में काफी महत्वपूर्णता स्थान अर्जित किया है, जिसके संबंध में यह स्वाभाविक है कि, एनबीएफसी क्षेत्र के नियम बदलते परिदृश्य के साथ तालमेल रखें और वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए बढ़ते इंटरलिंगेज और उभरते जोखिमों को संबोधित करने के लिए सरल नियामक दृष्टिकोण से अधिक कैलिब्रेटेड और सूक्ष्म दृष्टिकोण की ओर बढ़ें।

एनबीएफसी क्षेत्र में मामलों की स्थिति का जायजा लेना शायद सार्थक हो सकता है। एनबीएफसी के लिए एसबीआर

फ्रेमवर्क 22 अक्टूबर, 2021 को जारी किया गया था और यह 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी हो गया। आमतौर पर, इस तरह के सुधार के प्रभाव का आकलन केवल मध्यम से दीर्घकालिक अवधि में किया जा सकता है। हालांकि, प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि एसबीआर ढांचे की शुरुआत के बाद एनबीएफसी क्षेत्र मजबूत और लचीला हो गया है। उद्योग के साथ हमारी बातचीत से यह भी पता चलता है कि ढांचे ने आकार, जटिलता और परस्पर जुड़ाव के मापदंडों के आधार पर संस्थाओं पर आनुपातिक नियामक बोझ के इच्छित प्रभाव को प्राप्त किया है।

30 सितंबर, 2023 तक, बेस, मिडिल और अपर लेयर में एनबीएफसी की कुल परिसंपत्तियों में एनबीएफसी का क्रमशः 6 प्रतिशत, 71 प्रतिशत और 23 प्रतिशत हिस्सा था। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (एफएसआर)3 के नवीनतम संस्करण में कहा गया है कि एनबीएफसी द्वारा कुल ऋण सितंबर 2023 में एक साल पहले के 10.8 प्रतिशत से 20.8 प्रतिशत (वर्षानुवर्ष) बढ़ गया, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से व्यक्तिगत ऋण और उद्योग को ऋण द्वारा किया गया। एनबीएफसी का जीएनपीए अनुपात सितंबर 2023 में समग्र जीएनपीए अनुपात के साथ सभी क्षेत्रों में सुधार के साथ नीचे की ओर अग्रसर होना जारी रहा, जो सितंबर 2022 में 4.6 प्रतिशत की तुलना में 5.9 प्रतिशत था और एनएनपीए अनुपात सितंबर 2022 में 1.5 प्रतिशत की तुलना में 3.2 प्रतिशत था। एनबीएफसी की पूंजी पर्याप्तता भी इस दौरान 27.4 प्रतिशत से सुधरकर 27.6 प्रतिशत हो गई है। एनबीएफसी की लाभप्रदता में भी सुधार हुआ है, जो आरओए में 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 2.9 प्रतिशत होने से स्पष्ट है।

दृष्टिकोण के संदर्भ में, रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए तनाव परीक्षणों से पता चलता है कि समग्र क्षेत्र भविष्य के झटकों का सामना करने में सक्षम होगा। क्रेडिट जोखिम के लिए, बेसलाइन परिदृश्य के तहत, सेक्टर का एक साल आगे जीएनपीए अनुपात 3.8 प्रतिशत और सीआरएआर 22.0 प्रतिशत होने का अनुमान है, जबकि मध्यम झटके के तहत, सीआरएआर बेसलाइन के सापेक्ष लगभग 70 बीपीएस तक गिर सकता है और गंभीर झटके की स्थिति में, सेक्टर का पूंजी पर्याप्तता अनुपात बेसलाइन के सापेक्ष 101 बीपीएस तक 21.0 प्रतिशत तक घट सकता है। इसी

तरह, चलनिधि जोखिम के लिए, तनाव परीक्षण के परिणाम बताते हैं कि एनबीएफसी की संख्या जो बेसलाइन, मध्यम और उच्च जोखिम परिदृश्यों में अगले एक वर्ष में तरलता में नकारात्मक संचयी बेमेल का सामना करेगी, 6 नमूने की परिसंपत्ति का आकार क्रमशः (1.3 प्रतिशत), 17 (10.4 प्रतिशत) और 34 (15.0 प्रतिशत) था।

कुल मिलाकर एनबीएफसी क्षेत्र स्वस्थ, स्थिर और भविष्य के झटकों के लिए लचीला बना हुआ है। हालांकि, एफएसआर में यह भी कहा गया है कि पिछले चार वर्षों के दौरान, व्यक्तिगत ऋणों के लिए चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) (लगभग 33 प्रतिशत) एनबीएफसी क्षेत्र के लिए समग्र ऋण वृद्धि (लगभग 15 प्रतिशत) से कहीं अधिक हो गई है। चुनिंदा खुदरा ऋण श्रेणियों के जोखिम भारांक में हमारी हालिया वृद्धि को इस संदर्भ में देखा जा सकता है।

एनबीएफसी क्षेत्र के लिए नियामक दृष्टिकोण

एनबीएफसी क्षेत्र के लिए नियामक दृष्टिकोण पर चर्चा आरंभ करते हुए -

वित्तीय क्षेत्र के लिए विनियम बनाते समय, रिज़र्व बैंक हमेशा इस तथ्य के प्रति सचेत रहा है कि किसी वित्तीय संस्था के विनियमन का स्तर उस संस्था द्वारा उत्पन्न जोखिमों की अवधारणा और वित्तीय प्रणाली पर उसके परिचालनों के पैमाने के अनुरूप होना चाहिए। एनबीएफसी क्षेत्र के प्रति हमारा नियामक दृष्टिकोण वित्तीय स्थिरता की रक्षा और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए गतिविधि-आधारित और इकाई-आधारित नियमों के संयोजन द्वारा निर्देशित किया गया है। हमने अधिक व्यापक और लचीले नियामक ढांचे को प्राप्त करने के लिए इन दोनों दृष्टिकोणों की ताकत का लाभ उठाने की कोशिश की है। हम इस हाइब्रिड दृष्टिकोण को विशेष रूप से एक सतत विकसित एनबीएफसी क्षेत्र के लिए मूल्यवान पाते हैं, जहां नवाचार और नए व्यापार मॉडल लगातार उभर रहे हैं।

इकाई आधारित विनियमों में एक विशिष्ट वित्तीय संस्थान के समग्र जोखिम का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने का लाभ होता है और नकारात्मक बाह्यताओं को कम करने के लिए एक इकाई के भीतर विभिन्न गतिविधियों की परस्पर क्रिया से उत्पन्न होने वाले प्रणालीगत जोखिमों को संबोधित करने के लिए बेहतर स्थिति में है। नियामक के दृष्टिकोण से, इकाई-आधारित नियमों को लागू

³ <https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=1254>

करना आम तौर पर आसान होता है, क्योंकि नियमों को संस्थाओं के एक सेट पर समान रूप से लागू किया जाता है। हालांकि, इसका दूसरा पक्ष यह है कि इकाई-आधारित नियम विशिष्ट गतिविधियों को लक्षित करने में कम सटीक हो सकते हैं, बदलते परिदृश्य के अनुकूल होने के लिए धीमे हो सकते हैं, और कभी-कभी, संभावित रूप से कम जोखिम वाली गतिविधियों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकते हैं।

दूसरी ओर, गतिविधि-आधारित नियम, नियमकों को उच्च जोखिम वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाकर संभावित जोखिम भरी वित्तीय गतिविधियों के अधिक सटीक लक्ष्यीकरण की अनुमति देते हैं, जो इसमें शामिल संस्था के प्रकार की परवाह किए बिना किया जाता है। संभावित नकारात्मक पक्ष यह है कि इस तरह के दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप एक खंडित नियामक परिदृश्य हो सकता है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों के लिए अलग-अलग नियम हैं, जो संभावित रूप से निरीक्षण को और अधिक जटिल बना सकते हैं। कभी-कभी, कई गतिविधियों के संयोजन से उत्पन्न होने वाले प्रणालीगत जोखिम अनिर्धारित रह सकते हैं।

इस बात पर बल दिया गया है कि आदर्श रूप से, समान जोखिम, समान कार्यकलाप, समान विनियम का सिद्धांत लागू होना चाहिए अर्थात् विनियामक विवाचन से बचने के लिए समान कार्यकलाप करने वाली संस्थाओं के लिए समान विनियम होना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है - यदि यह एक बतख की तरह दिखता है, एक बतख की तरह बोलता है और एक बतख की तरह ही काम करता है तो शायद यह एक बतख ही है - और इसे बतख के रूप में ही विनियमित किया जाना चाहिए। हालांकि, इस दृष्टिकोण को प्रभावी लेकिन गैर-दमघोटू नियमों के लिए उपयुक्त रूप से जाँचे -परखे जाने की आवश्यकता है। सभी वित्तीय संस्थाओं के लिए उनके परिचालनों के पैमाने को ध्यान में रखे बिना विनियमों के एक ही सेट को लागू करने के संकीर्ण दृष्टिकोण का अनुसरण करने के बजाय, वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त हो सकता है।

हम इस तथ्य से अवगत हैं कि एनबीएफसी विशिष्ट गतिविधियों में संलग्न हैं, प्रत्येक अपने अद्वितीय जोखिम को वहन करती है, और हाइब्रिड मॉडल में निहित लचीलेपन ने हमें इकाई-आधारित नियमों में निहित व्यापक प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन

का त्याग किए बिना इस क्षेत्र में बदलावों के लिए तेजी से अनुकूलन करने में सक्षम बनाया है। इस संतुलन को ध्यान में रखते हुए, हमारा नियामक दृष्टिकोण दो व्यापक श्रेणियों में विकसित हुआ है - विवेकपूर्ण विनियम और व्यवसाय विनियम का संचालन। जबकि विवेकपूर्ण विनियमन वित्तीय संस्थाओं और समग्र वित्तीय प्रणाली की शोधन क्षमता, सुरक्षा और सुदृढ़ता पर केंद्रित है, व्यापार विनियमन का संचालन इस बात पर केंद्रित है कि वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहकों और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं के साथ कैसे व्यवहार करती हैं। वर्तमान नियामक परिदृश्य विवेकपूर्ण और आचरण नियमों के स्तंभों के तहत इकाई और गतिविधि-आधारित दृष्टिकोणों का एक संयोजन है।

मैं एनबीएफसी क्षेत्र में कुछ हालिया नियमों का हवाला देना चाहूंगा जिनमें हमने विभिन्न विनियामक दृष्टिकोणों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है:

- बिंदु में पहला मामला, मैं पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (एनबीएफसी-पी 2 पी) का उल्लेख करना चाहूंगा: चूंकि एनबीएफसी-पीटूपी खुद पर कोई क्रेडिट जोखिम नहीं लेते हैं और केवल उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के लिए बैठक की जगह के रूप में कार्य कर रहे हैं, एनबीएफसी-पी 2 पी के लिए विवेकपूर्ण नियमों को बुनियादी प्रवेश स्तर की आवश्यकताओं पर बहुत हल्का रखा गया है। दूसरी ओर, जैसा कि एनबीएफसी-पी 2 पी पर लेंडर उधारकर्ताओं को जानने के लिए प्लेटफार्मों पर भरोसा करते हैं, और केवाईसी प्रमाणीकरण, क्रेडिट स्कोरिंग, कानूनी औपचारिकताओं, वसूली सहायता आदि जैसी अतिरिक्त सेवाओं का लाभ उठाते हैं। इसलिए, इन प्लेटफार्मों के लिए आचरण मानदंडों को वित्तीय क्षेत्र में अन्य विनियमित संस्थाओं के बराबर रखा गया है।
- दूसरा उदाहरण माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र का है। माइक्रोफाइनेंस ऋण छोटे आकार के ऋण हैं और समग्र ऋण में इनकी बहुत कम हिस्सेदारी है। इसलिए माइक्रोफाइनेंस लोन से वित्तीय स्थिरता की चिंता की संभावना काफी कम है। हालांकि, संख्या के संदर्भ में, माइक्रोफाइनेंस ऋण बड़ी संख्या में उधारकर्ताओं को प्रभावित करते हैं और ये उधारकर्ता कमजोर श्रेणी के

होते हैं। इसलिए, यह आवश्यक हो जाता है कि माइक्रोफाइनेंस ऋणों के लिए नियामक दृष्टिकोण विशेष रूप से इन उधारकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लक्षित हो। ग्राहक संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, सभी विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए माइक्रोफाइनेंस ऋणों के लिए एक इकाई-एग्नोस्टिक और गतिविधि-आधारित व्यापक नियामक ढांचा स्थापित किया गया है।

- तीसरा उदाहरण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड-एनबीएफसी (आईडीएफ-एनबीएफसी) के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का है। हाल ही में, हमने आईडीएफ-एनबीएफसी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा की है जिसमें अवसंरचना वित्तपोषण की गतिविधि के लिए विनियामक दिशानिर्देशों को अवसंरचना वित्तपोषण में लगी एनबीएफसी की अन्य श्रेणियों के साथ यथासंभव सामंजस्यपूर्ण बनाया गया है। तदनुसार, हमने आईडीएफ-एनबीएफसी के लिए एक प्रायोजक की आवश्यकता को वापस ले लिया है और उनकी नियामक पूंजी आवश्यकता और जोखिम मानदंडों को एनबीएफसी-आईएफसी और एनबीएफसी-आईसीसी के साथ मध्य स्तर में संरेखित किया है। यह दृष्टिकोण आईडीएफ-एनबीएफसी के अद्वितीय कम जोखिम वाले चरित्र को संरक्षित करते हुए बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण एनबीएफसी पर लागू नियमों के सामंजस्य की अनुमति देता है।

क्या अपर लेयर एनबीएफसी बैंकों के बराबर विनियमित हैं?

अब, एनबीएफसी क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर आते हुए, मैं दो प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करता हूँ-

सबसे पहले, कुछ रिपोर्टें और चर्चाएं हुई हैं कि एनबीएफसी के लिए नियम, विशेष रूप से ऊपरी स्तर में एनबीएफसी के लिए, बैंकों के बराबर बनाए गए हैं। मैं इस अवसर का उपयोग इस मामले में सीधे अभिलेख स्थापित करने के लिए करना चाहूंगा। हालांकि इस बात पर सहमति है कि बैंकों और एनबीएफसी के बीच विनियमों को कुछ क्षेत्रों में सुसंगत बनाया गया है और कुछ एनबीएफसी के लिए विशेष रूप से ऊपरी स्तर की एनबीएफसी

के लिए एसबीआर के तहत मजबूत किए गए हैं, बैंकों और एनबीएफसी पर लागू नियमों के बीच ढांचे में महत्वपूर्ण अंतर मौजूद हैं। मैं इस पर जोर देने के लिए उनमें से कुछ पर प्रकाश डालना चाहूंगा-

- एक सार्वभौमिक बैंक के लिए न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी आवश्यकता एनबीएफसी के लिए ₹ 10 करोड़ की तुलना में ₹ 1000 करोड़ है। साथ ही, बैंकिंग लाइसेंस आवेदक के लिए संवीक्षा एनबीएफसी लाइसेंस आवेदक की जांच की तुलना में कहीं अधिक कठोर होती है, जो मुख्य रूप से बैंक लाइसेंस के माध्यम से सार्वजनिक जमा की पहुंच को दर्शाती है। एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए, शायद यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि आरबीआई ने पिछले पांच वर्षों में 447 एनबीएफसी को पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया है, जबकि कोई सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस नहीं दिया गया है और इस अवधि के दौरान केवल 2 लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को लाइसेंस दिए गए हैं।
- दूसरा बड़ा अंतर यह है कि बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत विशेष रूप से प्रदान की गई गतिविधियों के अलावा किसी भी अन्य गतिविधियों में संलग्न नहीं हो सकते हैं। जबकि एनबीएफसी के नियमों को नियंत्रित करने वाले आरबीआई अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही, बैंकों से अपेक्षित है कि वे समायोजित निवल बैंक ऋण का न्यूनतम 40 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लिए लगाएं और लघु वित्त बैंकों के लिए यह आवश्यकता और भी अधिक 75 प्रतिशत है। एनबीएफसी की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।
- कभी-कभी यह भी तर्क दिया जाता है कि एनबीएफसी की नियामकीय पूंजी आवश्यकता बैंकों के लिए 9 प्रतिशत की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि बैंकों की पूंजी आवश्यकता में क्रेडिट, बाजार और परिचालन जोखिम पूंजी शुल्क शामिल हैं, जबकि एनबीएफसी (ऊपरी परत में एनबीएफसी सहित) के लिए, पूंजी की आवश्यकता केवल क्रेडिट जोखिम पूंजी प्रभार पर आधारित है। यहां तक कि विनियामक पूंजी के घटक

⁴ एनबीएफसी-इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां (एनबीएफसी-आईएफसी) और एनबीएफसी-इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनियां (एनबीएफसी-आईसीसी)।

भी उतने विस्तृत रूप से निर्धारित नहीं किए गए हैं जितना कि बैंकों के मामले में है।

- एनबीएफसी के संचालन के लिए लगभग कोई नियामक प्रतिबंध नहीं हैं। दूसरी ओर, वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत शाखा प्राधिकरण नीति के अधीन किया जाता है, जिसमें वे शाखाएं खोल सकते हैं। एनबीएफसी (एनबीएफसी-यूएल सहित) के लिए कोई अनुरूप दिशानिर्देश नहीं हैं।

संक्षेप में, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि एनबीएफसी (विशेष रूप से ऊपरी स्तर में) के लिए नियम बहुत अधिक कैलिब्रेटेड हैं और निश्चित रूप से बैंकों पर लागू नियमों के बराबर नहीं हैं।

क्या एनबीएफसी को डिपॉजिट स्वीकार करने की अनुमति दी जानी चाहिए?

दूसरा मुद्दा जिस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा वह एनबीएफसी की जमा स्वीकार करने की गतिविधि से संबंधित है।

इस धारणा के साथ कि एसबीआर ढांचे ने एनबीएफसी के नियमों को अधिक बैंक जैसा बना दिया है, यह भी समय-समय पर मांग की जाती रही है कि एनबीएफसी को सार्वजनिक जमा स्वीकार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पहले मुद्दे को स्पष्ट करने के बाद, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि वास्तव में एनबीएफसी द्वारा सार्वजनिक जमाराशियों को स्वीकार न किया जाना ही रिजर्व बैंक को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए कम प्रवेश बाधाओं को रखने की विनियामक सुविधा प्रदान करता है, उन्हें अपनी पसंद के किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने की अनुमति देता है और अपने कारोबार को बंद करने के लिए निकास बाधाओं को कम करता है।

जमाराशि की स्वीकृति, चाहे वह किसी भी तरीके और रूप में हो, जमा बीमा और केंद्रीय बैंक तरलता बैकस्टॉप सहित एक मैक्रो वित्तीय सुरक्षा नेट के अस्तित्व की आवश्यकता होती है। ये सुरक्षा जाल बढ़ी हुई नियामक कठोरता और गहन पर्यवेक्षी निरीक्षण के साथ आते हैं। एनबीएफसी विशिष्ट आर्थिक कार्य करने वाली एक आला कंपनी के रूप में विकसित हुए हैं और उनके लिए बैंक की तरह बनने की मांग करना असामान्य है।

इसे ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ने वर्ष 1997 से जनता की जमाराशियाँ स्वीकार करने के लिए नई गैर-बैंकिंग वित्तीय

कंपनियों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया है। इसके विपरीत, रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण एनबीएफसी की डिपॉजिट लेने की गतिविधियों को हतोत्साहित करना रहा है, जैसा कि पिछले दशक में डिपॉजिट लेने वाली एनबीएफसी की संख्या में मार्च 2014 में 241 से सितंबर 2023 में 26 तक की कमी से स्पष्ट है।

चिंताएं और अपेक्षाएं

एनबीएफसी क्षेत्र अपने शुरुआती दिनों से एक लंबा सफर तय कर चुका है और एनबीएफसी क्षेत्र के लिए नियामक ढांचे ने परिचालन लचीलापन और आनुपातिक नियम प्रदान करके इसके विकास में सहायता की है। हालांकि, कुछ जोखिम हैं और मैं इस मंच का उपयोग एनबीएफसी से आग्रह करने के लिए करना चाहूंगा कि वे अपने व्यापार मॉडल या बैलेंस शीट में इन जोखिमों की निगरानी करें और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक कार्रवाई शुरू करें:

- एनबीएफसी वित्तीय प्रणाली से धन के बड़े शुद्ध उधारकर्ता हैं, जिनमें बैंकों में सबसे अधिक जोखिम है। कई एनबीएफसी कई बैंकों के साथ उधार संबंध बनाए रखते हैं। बैंक अपने डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्रों की सदस्यता भी लेते हैं। उच्च उत्तोलन के साथ इस तरह के केंद्रित लिंकेज वित्तीय प्रणाली में छूट के जोखिम पैदा कर सकते हैं। एनबीएफसी के लिए धन स्रोतों का संकेंद्रण भी एक विवेकपूर्ण रणनीति नहीं है क्योंकि उन्हें तनाव की घटनाओं के दौरान इस तरह के वित्तपोषण के अचानक सूखने का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, एनबीएफसी के लिए अपने फंडिंग स्रोतों को व्यापक बनाने और बैंक ऋण पर अधिक निर्भरता को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना विवेकपूर्ण हो सकता है।
- उच्च विकास के अनुसरण में, एनबीएफसी के बीच ग्राहकों को ओवरसिम्प्लिफाइड अंडरराइटिंग प्रक्रियाओं के साथ बोर्ड पर लाने की प्रवृत्ति प्रतीत होती है। जबकि उधारकर्ता के लिए आसानी और सुविधा बहुत महत्वपूर्ण है, यह अंडरराइटिंग मानकों की कीमत पर नहीं आना चाहिए। ऋण देने में आसानी में सुधार के अलावा, एनबीएफसी को अपने ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता बनाए रखने पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

- हाल ही में, एनबीएफसी-पी 2 पी की कुछ व्यावसायिक प्रथाएं नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं लगती हैं। एनबीएफसी-पी2पी पर उधारदाताओं का एक बड़ा हिस्सा व्यक्ति है और उनसे ऋण प्रदान करने में शामिल जोखिमों को समझने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित होने की उम्मीद नहीं है। उधार गतिविधि में निहित जोखिमों के बारे में उधारदाताओं को शिक्षित करने के बजाय, एनबीएफसी-पी 2 पी को विभिन्न माध्यमों से जोखिमों को कम करने के लिए देखा गया है जैसे कि उच्च/सुनिश्चित रिटर्न का वादा करना, लेनदेन की संरचना करना, किसी भी समय फंड रि कॉल सुविधाएं प्रदान करना आदि। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ कि लाइसेंसिंग शर्तों और विनियामक दिशानिर्देशों का कोई भी उल्लंघन अस्वीकार्य है।
- माइक्रोफाइनेंस ऋणों के लिए संशोधित ढांचे के तहत, ऋणों के मूल्य निर्धारण पर नियम-आधारित निर्देशों को एक सिद्धांत-आधारित ढांचे के साथ बदल दिया गया था, जिसमें प्रकटीकरण और पारदर्शिता की आवश्यकताएं थीं। यह देखा गया है कि ऋणदाताओं ने उधारकर्ताओं को बढ़ी हुई लागत को पारित करने में तेजी दिखाई, लेकिन वे नए ढांचे के तहत परिकल्पित लाभों को पारित करने के लिए अनिच्छुक रहे हैं। कुछ एमएफआई ने नई व्यवस्था में अपने मार्जिन में असंगत रूप से वृद्धि की है। हम सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को प्रदान की गई स्वतंत्रता के दुरुपयोग से बेखबर नहीं हैं और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार हमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे।
- मार्च 2023 के बाद अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग क्षेत्र में उथल-पुथल के बाद, फाइनेंशियल संस्थाओं के बिज़नेस मॉडल बढ़ी हुई जांच के दायरे में आ गए हैं, हमने कुछ एनबीएफसी में केंद्रित व्यवसाय मॉडल भी देखे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ एनबीएफसी ने उपभोक्ता ऋण, वाहन ऋण आदि जैसे क्षेत्रों में निवेश केंद्रित किया है। यदि इनमें से कोई भी खंड आर्थिक तनाव का सामना करता है, तो उन एनबीएफसी के वित्त पर

महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और बदले में, बैंकों सहित उनके उधारदाताओं पर। यह उनके हित में है कि संस्थाओं को इन जोखिमों पर विचार करना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि बोर्ड ऐसे मुद्दों पर ध्यान रखें।

- अंत में, डिजिटल माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करने पर एनबीएफसी की बढ़ती निर्भरता और फिनटेक के साथ उनकी साझेदारी को देखते हुए, साइबर सुरक्षा खतरों और परिचालन व्यवधानों सहित प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिमों के प्रति क्षेत्र का जोखिम काफी बढ़ गया है, साथ ही साथ तीसरे पक्ष की साझेदारी पर उनकी निर्भरता में काफी वृद्धि हुई है। इसलिए, हम उम्मीद करते हैं कि संस्थाएं अपने व्यवसाय और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप उपयुक्त जोखिम शमन उपाय करेंगी, भले ही इसका मतलब नियामक न्यूनतम आवश्यकताओं से परे जाना हो।

समापन विचार

हमने हाल ही में स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) के लिए सर्वव्यापी ढांचे का मसौदा तैयार किया है। एसआरओ से अनुपालन संस्कृति में सुधार करने के साथ-साथ नैतिक व्यापार पद्धतियों, ग्राहक संरक्षण, बेहतर शासन मानकों, ध्वनि जोखिम प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देने और एनबीएफसी सहित वित्तीय क्षेत्र के व्यवस्थित विकास में सकारात्मक योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

एनबीएफसी क्षेत्र भारतीय वित्तीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हितधारक है। एनबीएफसी क्षेत्र का सुदृढ़ विनियमन और बेहतर निगरानी न केवल वित्तीय प्रणाली बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था में एनबीएफसी के महत्व का सबसे अच्छा प्रमाण है। अब समय आ गया है कि एनबीएफसी क्षेत्र अपनी छाया के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र की छाया से भी बाहर आए। मुझे यकीन है कि एनबीएफसी आगे चलकर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

धन्यवाद।